में उभरी कंपनी 'SophosLabs' के अनुसार भारत दुनिया में साइबर अटैक्स की दृष्टि से पांचवां सबसे संवेदनशील, fifth most vulnerable देश है। आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार इस संदर्भ में तत्काल आवश्यक कदम उठाए और देश को आश्वस्त करे।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): सर, मैं इनके उल्लेख से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): सर, मैं भी इनके उल्लेख से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu) : Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): सर, मैं भी इनके उल्लेख से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : महोदय, मैं भी इनके उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Yes, all the names should be added.

Concern over salinity ingress and drying up of Narmada River

श्री अहमद पटेल (गुजरात): मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं जिस प्रदेश का वासी हूं, नर्मदा नदी वहीं से बहती है। अभी मानसून है, इसलिए नर्मदा नदी में पानी है, लेकिन जैसे ही वर्षा खत्म हो जाएगी, वहां पर पानी बहुत कम जाता है। जिस नर्मदा नदी की चौड़ाई 1.5 किलोमीटर थी, वह घट कर सिर्फ 400 मीटर रह गई है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसका प्रवाह कम हो गया है, यह नदी सिकुड़ कर रह गई है, उसकी विड्थ कम हो गई है, उसकी वजह से समुद्र का पानी नर्मदा नदी में आ जाता है, जिसकी वजह से क्षार पैदा हो जाता है।

यह नर्मदा नदी न सिर्फ श्रद्धा, आस्था या विश्वास का एक प्रतीक है, बल्कि लोगों की आजीविका का भी साधन है। जो वहां के किसान, उद्योग, और मछुआरे हैं उनको, और जो बाकी पीने के पानी की व्यवस्था है, उससे वहां काफी तकलीफ पैदा हो गई है। जिस तरह से वहां दोनों किनारों पर जमीन का इरोज़न हो रहा है, उसकी वजह से खास तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी खेती को भी काफी नुकसान हो रहा है। उधर सरदार सरोवर डैम से लेकर नर्मदा नदी का जो मुहाना है, उसके बीच में जो 45 किलोमीटर का विस्तार है, खास तौर पर वहां जहां वर्षा नहीं होती है, सूखे से वह एरिया प्रभावित हो जाता है, वहां पानी की तकलीफ हो जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और अनुरोध भी करना चाहूंगा कि एक्सपर्ट टीम वहां भेजी जाए और सरदार सरोवर डैम से टाइम टू टाइम पानी छोड़ा जाए। जब वहां के मीडिया ने आवाज उठाई और हम लोगों ने आवाज उठाई, तब जाकर पांच हजार क्यूसेक पानी उसमें छोड़ा गया। हालांकि पहले रोजाना सिर्फ छह सौ क्यूसेक पानी

छोड़ा जाता था। तो एक एक्सपर्ट कमेटी वहां भेजी जाए, टाइम टू टाइम पानी छोड़ा जाए और उसके साथ-साथ दोनों किनारों पर प्रोटेक्शन वॉल बनानी चाहिए, ताकि लोगों की जमीन बच सके और जैसा पर्यावरणविदों ने कहा कि दोनों किनारों पर प्लांटेशन होना चाहिए और एक अवरोधक बनाना चाहिए, खास तौर पर जो मुहाना है, उसके आगे इसे बनाना चाहिए, ताकि समुद्र का जो पानी है, वह नदी में न आ सके। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इस पर त्वरित कार्यवाही की जाए और एक्सपर्ट टीम वहां भेजी जाए, ताकि नर्मदा नदी को बचाया जा सके, धन्यवाद।

श्री मोती लाल वोरा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल (गुजरात): महोदय, मैं भी इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं भी अपने आपको इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

Concern over slow progress of work on construction of NH-33 in Jharkhand

डा. प्रदीप कुमार बालमुचू (झारखंड): उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान झारखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। झारखंड में एनएच-33, जो रांची से ओडिशा और बंगाल को जोड़ता है, हम यह कह सकते हैं कि यह झारखंड की लाइफलाइन है। इसको दो फेज में फोर लेन कराया जा रहा है, फर्स्ट फेज में रांची से महुलिया तक और दूसरा फेज महुलिया से लेकर बंगाल-ओडिशा बॉर्डर तक है। फर्स्ट फेज में चार साल पहले इस एनएच का काम शुरू हुआ था, आज तक वह काम अधूरा पड़ा हुआ है और हमें ऐसी उम्मीद भी नहीं लगती कि आने वाले डेढ़-दो साल में वह काम पूरा हो जाएगा। इसके चलते लोगों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। रास्ते का रिपेयर भी नहीं हो रहा और साथ में फोर लेन का काम भी चल रहा है। दूसरे फेज की अगर बात करें, तो दूसरा फेज अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी जमीन ली जा रही है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो सेकंड फेज है, उसमें जमीन का मुआवजा वहां के जो आदिवासी, ग्रामीण लोग हैं, उनको एक हजार रुपए से तेरह सौ रुपए डिस्मिल दिया जा रहा है। हमें लगता है कि इस देश में कहीं भी, अगर आप झारखंड के जंगल में भी कहीं जमीन लीजिएगा, तो ग्यारह सौ रुपए से बारह सौ रुपए के डिस्मिल रेट में